पालिका कर्मचारी संघ ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की

करनाल, (म.मो.) सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को करनाल में नगरपालिका कर्मचारी संघ ने गेट मीटिंग कर विरोध जाहिर किया। आगामी आंदोलन का नोटिस संयुक्त आयुक्त को सौंपा गया। मीटिंग की अध्यक्षता प्रधान राम सिंह ने की। इस मौके पर राज्य सचिव शारदा व जिला प्रधान वीरभान बिडलान ने कहा कि राज्य सरकार मजदूर, कर्मचारी व किसान विरोधी नीतियां लगातार लागू कर रही है। इस कारण महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार बढ़ा है। सरकार निजीकरण की ओर से ध्यान दे रही है। सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नगरपालिका कर्मचारी संघ के साथ अधिकारियों ने कई बार समझौते किए मगर आज तक लागू नहीं किया गया।

आंदोलन की रूपरेखा के बारे में उन्होंने कहा कि 30 जुलाई तक राज्य कमेटी के पांच जत्थे प्रदेश के सभी कर्मचारियों से संपर्क करेंगे। 31 जुलाई को नोटिस डे के रूप में मनाया जाएगा। 27 अगस्त को सामूहिक अवकाश रखा जाएगा। इसी बीच 17 अगस्त को झाड़ू प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्य रमेश दादूपुर, करनाल उपप्रधान विनोद प्रोचा, इकाई उपप्रधान संदीप त्यागी, ज्वाइंट डिप्टी सेकेट्री प्रवेश प्रोचा, संगठनकर्ता सुमेर चंद, सह सचिव रोहताश आदि मौजूद रहे।

तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेसियों का अभियान

करनाल, (म.मो.) पेट्रोल-डीजल के बढ़ते रेट के खिलाफ कांग्रेस ने आज पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। पेट्रोल पम्पों पर कांग्रेसियों ने लोगों से बढ़ते तेल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर करवाए। ये अभियान हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिला। कांग्रेस के विधायक सरकार को चारों तरफ से बढ़ते तेल के दामों को लेकर घेरने में जुटे हुए थे। इस मौके पर विधायक शमशेर सिंह गोगी, सुरेश गुप्ता और जोगिन्द्र ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी में खासा रोष है और ये रोष मीडिया के कैमरों पर भी निकलता है। जनता सरकार को कोसती हुई नजर आती है। करनाल में पेट्रोल के दाम 100 रुपये और डीजल 90 रुपये के पार पहुंच गया है। अगर इसी रफ्तार से तेल के दाम बढ़ते गए तो आम आदमी की जेब खाली ही नजर आएगी।

मिड-डे मील वर्करों ने कहा, 24 हजार वेतन, काम की उम्र 65 तक करो

करनाल, (म.मो.) मिड डे मील वर्करों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें 24 हजार रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। वर्कर को 65 साल की उम्र तक काम करने की अनमुति हो। इसके अलावा लगभग 10 मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर यूनियन ने फव्वारा पार्क के योग शेड में सभा की। वर्करों की योजना जिला सचिवालय तक प्रदर्शन करने की थी, मगर तेज बरसात के चलते सभा स्थल पर ही नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

इस मौके पर मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जय भगवान, जिला प्रधान शिमला व सीटू जिला प्रधान सतपाल सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करती है, लेकिन देश की 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स को भुखमरी की कगार पर छोड़ रखा है। लंबे समय से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। 45 वें श्रम सम्मेलन को सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है जो मिड डे मील वर्कर्स के कर्मचारी बनाने, न्यूनतम वेतन लागू करने और समाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है।

उन्होंने कहा कि एक तरफ कुपोषण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मिड डे मिल के बजट में केंद्र सरकार ने 25 प्रतिशत कटौती कर दी है। मांग की गई कि रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो व कम से कम 2 लाख रुपये लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्करों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें चार महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। शिक्षा विभाग व सरकार वर्कर के भारी उपेक्षा कर रही है। साल भर से वर्दी, भत्ते नही मिल रहे। जो भी वर्कर हटाई गई हैं उन्हें दोबारा काम पर रखा जाए। वर्कर से किसी प्रकार की बेगार न हो। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने मजदूरों के बारे में चार नए लेबर कोड लाकर मजदूरों की वर्तमान और भावी पीढ़ी को गुलामी की दलदल में धकेल दिया है। खेती और खाद्य सुरक्षा को उजाड़ने वाले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लाखों किसान सड़कों पर हैं। लेकिन सरकार चंद पूंजीपतियों की गोद में खेल रही है। हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत इन कानूनों को वापस ले। मिड डे मिल वर्कर्स ने तय किया कि नौ अगस्त की मजदूर किसानों की जिला स्तर पर होने वाली लामबंदी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी।

इस अवसर पर सीटू उपाध्यक्ष ओपी माटा, मिड डे मिल यूनियन की जिला नेताओं, कमलेश, मीना, पालो, कविता, राम कुमारी, शीला, आरती, रेखा, पुष्पा, पालो देवी व बबीता ने वर्करों को संबोधित किया।

बेदखली सूचना

मैं, हरद्वारी लाल पुत्र गणेशी लाल निवासी मकान नं. 2436, आम्बेडकर नगर, सदर बाजार, करनाल का रहने वाला हूं। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मैं इस पते का स्थायी निवासी हूं। मेरा पुत्र अजय कुमार और मेरी पुत्रवधू डिम्पी जो कि वह दोनों हमारे कहने-सुनने में नहीं हैं। इन दोनों का व्यवहार मेरे व मेरे परिवार के प्रति ठीक नहीं है। इनके गलत व्यवहार को देखते हुए मैं इन दोनों को अपनी चल/अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं। इनके साथ मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इनके साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन करने वाला खुद जिम्मेदार होगा। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

हरद्वारी लाल
2436, आम्बेडकर नगर, सदर बाजार, करनाल

चढ़ूनी गुट के नेताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के बहिष्कार का ऐलान किया

भाजपा जो चाहती थी, वही हुआ, फूट पड़ गई किसान आंदोलन में

करनाल, (जेके शर्मा) संयुक्त किसान मोर्चा से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के निलंबन पर चढ़ूनी ग्रुप के किसान नेताओं में नाराजगी बढ़ गई है। चढ़ूनी के निलंबन पर चढ़ूनी ग्रुप के किसानों ने एक सप्ताह के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का बहिष्कार करने का ऐलान कर सीधे-सीधे संयुक्त किसान मोर्चा को चेतावनी दे डाली। किसान नेताओं ने कहा कि गुरनाम सिंह के आह्वान पर किसानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए न के वल पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में सरकार द्वारा लगाए गए बैरियर तोड़े, बल्कि सीएम को कार्यक्रम तक नहीं करने दिया। इतना ही नहीं भाजपा व जजपा नेताओं को कार्यक्रम न कर देने में भी अहम् भूमिका निभाई। इसके बावजूद उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जो निन्दनीय है।

बीकेयू चढ़ूनी करनाल के वाट्स ग्रुप में संयुक्त किसान मोर्चा के बहिष्कार का संदेश भी डाल दिया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसके ग्रुप एडमिन हैं और चुनिंदा तीन-चार लोग ही इस ग्रुप में संदेश डाल सकते हैं।

बता दें कि कल भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पंजाब चुनाव के संबंध में दिए गए उनके बयान को लेकर सात दिनों के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। चढ़ूनी ने सुझाव दिया था कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल पंजाब के किसान संगठनों को अगले साल राज्य विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए।

संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया कि वह भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपने पूर्व नियोजित विरोध के साथ आगे बढ़ेगा, जहां 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि चढ़ूनी को कई बार ऐसा नहीं करने के लिए कहे जाने के बावजूद अपने मिशन पंजाब के बारे में बयान दे रहे हैं। राजेवाल ने कहा, फिलहाल हम केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। चढ़ूनी के बयान को लेकर राजेवाल ने चढ़ूनी को सात दिन के लिए निलंबित करने का ऐलान करते हुए कहा था कि वह कोई बयान जारी नहीं कर पाएंगे या मंच साझा नहीं कर पाएंगे। उन पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।

बहरहाल, इस बयान के बाद भी चढ़ूनी ने अपना बयान जारी कर अपने निलम्बन को गलत बताकर अपनी निजी राय के अधिकार से वंचित न करने का राग अलाप कर मोर्चा के नेताओं की इस कार्रवाई को ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने कहा कि विचार रखने के लिए मुझे निलंबित करना गलत था। फिर भी उन्होंने जो फैसला लिया है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा रुख अब भी वही है कि हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए। अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब में प्रदर्शनकारी, ईमानदार लोगों, मजदूरों, किसानों और छोटे दुकानदारों को अपनी सरकार बनानी चाहिए और पारंपरिक पार्टियों को हराना चाहिए। ऐसा करके इसे देश के सामने एक मॉडल के रूप में पेश करें। आज हमें एक दल से दूसरे दल में शासन बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और सत्ता से व्यवस्था को बदला जा सकता है।

गौरतलब है कि चढ़ूनी ने एक सप्ताह पहले कहा था कि केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल पंजाब के संगठनों को पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने सितंबर में महापंचायत और उत्तर प्रदेश में अन्य गतिविधियों की योजना बनाई है।

संयुक्त किसान मोर्चा की इस कार्रवाई के बाद करनाल जिले में चढ़ूनी ग्रुप के किसानों ने जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा का एक सप्ताह के लिए बहिष्कार कर बागी तेवर दिखाए है, उससे किसान आंदोलन की एकता की ताकत की दीवारें हिलने लगी हैं। भाजपा के लोग भी ये ही चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन रास्ता भटक जाए। किसानों के इस रवैये को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

सरकार किसानों को डराना नहीं, मारना चाहती है : चढ़ूनी

इन्द्री, (म.मो.) भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि किसान तो सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार शर्त लगाकर किसानों से बात नहीं करना चाहती। ऐसा लगता है कि सरकार किसानों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें मारना चाहती है। सत्ता में बैठे हुए नेता कहते कुछ हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। किसान अब संसद पर जाएंगे और संसद के बाहर ही अपनी संसद चलाएंगे। संसद भवन के अंदर सत्ताधारियों की संसद चलेगी तो बाहर किसान संसद चलाएंगे।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि या तो सरकार किसानों की बात माने नहीं तो फिर दोनों तरफ से तबाही होगी। जिसकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की होगी। सत्ता के लिए तीसरे मोर्चे के गठन में किसान यूनियन की भागीदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन क्या जनता ऐसे ही लुटती बढ़ती रहेगी। इन लोगों के चुंगल से बचने के लिए तो जनता को ही आगे आना होगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बुरी तरह हारने के डर से ही हरियाणा में सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। किसानों के आंदोलन में जिसने साथ नहीं दिया और ना ही किसानों के इस धर्म युद्ध में खड़ा हुआ है, उसे कतई वोट नहीं देना और जो किसानों का साथ दे, किसान भी उसका साथ दें। जो किसान अब भी घर बैठे हैं, उन्हें आंदोलन के मैदान में आ जाना चाहिए। यदि वह अब भी मैदान में नहीं आए तो फिर आत्महत्या के लिए तैयार रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को बदनाम करने के लिए उन पर तरह-तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन आने वाले वक्त में झूठे आरोप लगाकर किसानों को बदनाम करने वालों को सबक जरूर सिखाया जाएगा।

इस मौके पर किसान नेता रामपाल चहल, मनजीत सिंह चौगांवा, सुरेंद्र सिंह आदि किसान नेता मौजूद थे। बाद में गुरनाम सिंह नबियाबाद गुरुद्वारे में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए चले गए। वहां भी उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ।

सर्व कर्मचारी संघ ने पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन किया

करनाल, (म.मो.) : सर्व कर्मचारी संघ ने डीए, पुरानी पेंशन बहाली व नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस काम पर लेने की मांग को लेकर फव्वारा पार्क के शेड में प्रदर्शन किया। मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता करनाल ब्लाक प्रधान भाग सिंह ने की।

प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह व राज्य कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण शर्मा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार लंबे समय से कर्मचारियों व आम जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति असंवेदनशील बनी है। पूंजीपतियों के हक में श्रम कानूनों को खत्म कर दिया। महंगाई भत्ते व एलटीसी पर सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा खत्म कर सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। सबके लिए कोविड की फ्री वैक्सीन का प्रबंध किया जाए। विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता बहाल की जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति व बिजली संशोधन बिल 2021 तथा रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल वापस लिया जाए।

इस अवसर पर ऑल हरियाणा पावर कार्पोरेशन वर्कर यूनियन के सर्कल सचिव राजेंद्र राणा, राज्य उपप्रधान राजेश कौशिक, हुडा कर्मचारी यूनियन के सर्कल प्रधान सेवाराम, रंगलाल संधु, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सियानंद परोचा, आदि मौजूद रहे।